गुजरात में वापी नदी पर उपरिपुल का निर्माण

4296. **श्री शोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वापी नदी पर उपरिपुल के निर्माण हेतु अनुमानित व्यय स्वीकृत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय व्यय के लिए स्वीकृति कब प्रदान हो गई थी ; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) अनुमान दिसंबर, 1992 में स्वीकृत किया गया था ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू कर दिए जाने के बाद ही रेलवे द्वारा पुल खास के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा ।

गोधरा-दोहाद-इन्दौर-देवास-नक्सी रेल लाइन

4297. **श्री लक्सी राम अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोधरा-दोहाद इन्दौर-देवास नक्सी रेल लाइन को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है और इस वर्ष के बजट में इस कार्य के लिये कितना प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए इन्दौर-महू-पीथमपुर रेल मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने संबंधी कार्य को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां , इसकी अनुमानित लागत 297.14 करोड रुपए है, मार्च, 1993 के अंत तक 14.45 करोड रुपए के परिव्यय की संभावना है, 1993-94 के बजट में एक करोड रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । दिसम्बर, 1992 तक हुई प्रगति 24% है ।

(ख) आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

Wages escalation claim

4298. SHRI ABDUL SAMAD SIDDIQUI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have withdrawn the letter regarding wages escalation claim in respect of CS crossings written to Ministry of Finance, cost account branch; and

(b) what are the details of the report of the cost account branch which have been accepted by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) and (b) The Chief Adviser (Cost), Department of Expenditure, Ministry of Finance, in his report No. 1354/CAL/6842 dated 20.1.1987 has recommended wage escalation claim in respect of a firm engaged in the manufacture and supply of CMS crossings, based on escalation factor of 0.1 per cent. However, in the subsequent report No 1441/CAL/7081 dated 29.6.1990 in respect of wage escalation claim

of another firm engaged in manufacture and supply of the same item, Chief Adviser (Cost) recommended wage escalation, worked out on the basis of actual date rather than adoping 0.1 per cent as done earlier. Both the methods of arriving at wage escalation are provided in the contract agreement. After examining the entire issue the Ministry of Railways decided that the wage escalation factor should be based on verification of actual data by the Chief Adviser (Cost).

बगहा और छितौनी के बीच पुल का पुनर्निर्माण कार्य

4299. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगहा और छितौनी के बीच पुल के पुनर्निर्माण कार्य पर आने वाली लागत की हिस्सेदारी का क्या प्रावधान है;

(ख) किस राज्य ने अपनी हिस्सेदारी नहीं दी है ; और

(ग) उक्त कार्य का कितना प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) बगहा और छितौनी के बीच रेल-एवं-सड़क पुल की लागत में जल संसाधन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों की हिस्सेदारी इस प्रकार रहेगी :

1. भूमि की लागत सहित गाइड बांधों और उनकी सुरक्षा जैसे पानी के बहाव को नियंत्रित करने संबंधी कार्यों की लागत जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा 5:3:2 के अनुपात में वहन की जाएगी ।

2. भूमि की लागत सहित रेल-एवं-सड़क पुल के लिए सामान्य उप-संरचना की लागत रेल मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा 2:1:1 के अनुपात में वहन की जायेगी ।

3. रेल पुल अधिरचना और रेलपथ की समूची लागत रेलवे द्वारा वहन की जाएगी ।

4. सडक पुल अधिरचना की लागत में उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार का बराबर का हिस्सा रहेगा ।

5. भूमि की लागत सहित खादर में दो पहुंच तटबंधों की लागत में रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार का हिस्सा 70% 15% 15% के अनुपात में रहेगा पिचिंग और टर्फिंग की लागत में रेलों और उ० प्र० तथा बिहार की राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 2:1:1 के अनुपात में रहेगी ।

6. खादर के भीतर सड़क का खड़ंजा बिछाने की लागत में दोनों राज्यों सरकारों का हिस्सा बराबर रहेगा, सेतु बंधन और ग्रेड प्रथक्करण, यदि कोई हो, सहित खादर के बाहर की सडक की लागत, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी ।

(ख) किसी भी अन्य सहभागीदार, यथा, जल संसाधन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने अभी तक अपने हिस्से की समूची राशि का भुगतान नहीं किया है ।

(ग) दिसम्बर, 1992 तक 39% ।

Revenue earnings by Railways

4300. SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI SUNIL BASU RAY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways have exhausted all avenues of revenue earnings and is poised for substantial fare hikes; and

(b) if so, which section is going to be provided with added comforts more — the upper class or the second class passengers?